दैनिक
CIN-No-UT4999RJ2020PTC0679
UN NO-200022186
राजस्थान,दिल्ली,छत्तीसगढ़ से एकसाथ प्रकाशित
RNI NO. RAJHIN/2023/89729

मरुधर विशेष

Marudharvishesh@gmail.com
मो. 9653906665

अंक 02/68 | जयपुर | 28 मार्च/2025 | शुक्रवार | मूल्य रु. 5 | पृष्ठ: 04

आरसीए में भाजपा नेताओं वाली कमेटी को नोटिस

खिलाड़ियों के पैसों से महंगे फोन खरीदने और सूट सिलवाने का आरोप

एजेंसी

जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। एडहॉक कमेटी को अब राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर पिछले एक साल में हुए खर्चों का ब्योरा मांगा है। आरोप है कि कमेटी पदाधिकारी अपने निजी खर्चों के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया कि वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। इसलिए पूरे मामले की जांच करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने कहा कि खर्चों की पूरी जानकारी मांगी गई है। वहीं नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। वर्तमान की एडहॉक कमेटी का गठन एक साल पहले किया गया था। नीरज कुमार पवन ने कहा- हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी सदस्य अब एडहॉक कमेटी में आए। वह अगले तीन महीने में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लंबित चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करे, ताकि क्रिकेट की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकें।

सुप्रीम कोर्ट बोला- पेड़ काटना इंसान की हत्या से बदतर

ताज महल के आस-पास 454 पेड़ काटे थे

एजेंसी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के ताज महल के आस-पास अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने को मंजूरी दी है। साथ ही जुर्माने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी या संस्थान से अनुमति लिए बिना पेड़ नहीं काट सकता।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति ने पेड़ काटने पर जुर्माना लगाने पर जुर्माना और कार्रवाई न करने की मांग की थी।

कानून और पेड़ों को हल्के में नहीं लिया जा सकता

बेंच ने सीनियर एडवोकेट एडीएन राव के सुझाव को स्वीकारा कि अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि कानून और पेड़ों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और न ही लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का बेंचमार्क भी तय किया है कि ऐसे मामलों में कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

454 पेड़ काटने पर प्रति पेड़ 1 लाख रुपए जुर्माना

न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसमें शिव शंकर अग्रवाल ने पिछले साल काटे गए 454 पेड़ों के लिए प्रति पेड़ 1 लाख रुपए (कुल 4.54 करोड़) का जुर्माना लगाया गया था। अग्रवाल का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल ने गलती स्वीकार कर ली है और माफी मांगी है। साथ ही कोर्ट से जुर्माना राशि कम करने का आग्रह किया है, जिसे उन्होंने बहुत ज्यादा बताया है।

लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास

भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे : शाह

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है।

ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

उन्होंने कहा, मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं। कहां रुक रहे हैं। क्या कर रहे हैं।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी।

सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस या बिजनेस के लिए भारत आना चाहते हैं। मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। जो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे उनसे गंभीरता से निपटा जाएगा। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है।

नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोक रहे

हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान हैं, सेना के अड्डे हैं, उनको दुनियाभर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते थे। पहले भी घुसपैठियों को रोका जाता था, लेकिन तब इसका नियम नहीं था। हममें हिम्मत है नियम बनाकर रोकने की। पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया गया है।

भारत आए विदेशियों की जानकारी पुख्ता होगी:

सुरक्षा की दृष्टि से ड्रग्स कार्टल, घुसपैठियों की कार्टल, हवाला व्यापारियों को समाप्त करने की व्यवस्था हम इस बिल में कर रहे हैं। पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट-वीजा अनिवार्य होगा। विदेशियों के रजिस्ट्रेशन को और पुख्ता किया जाएगा।

पहले ये कानून ब्रिटेन में बने थे अब नई संसद में

अप्रवासियों से जुड़े कानून 1920, 1930 और 1946, ब्रिटेन की संसद में बने थे। भारत का कानून अब भारत की नई संसद में बन रहा।

विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए चौकियां बढ़ाईं

विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए हमने 73 अप्रवासन चौकियां बढ़ाई हैं। 2024 में आठ करोड़ 12 लाख आवाजाही हुई है। फास्टैग अप्रवासन यात्री कार्यक्रम हमने आठ एयरपोर्ट पर लागू किया है, जिसमें यात्रियों की जांच में 30 सेकंड समय लगेगा।

फेंसिंग के लिए ममताजी नहीं दे रहीं जमीन

पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। 450 किमी आपकी कृपा से खुली सीमा है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं और देशभर में फैल जाते हैं। जितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, सबके पास 24 परगना के आधार कार्ड मिले हैं। जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। ये फेंसिंग रुकी है तो केवल बंगाल सरकार के कारण रुकी है। ममताजी भूमि दे दें तो हम 450 किलोमीटर फेंसिंग कर देंगे।

विदेशियों को ब्लैक लिस्ट कानून के हिसाब से होगा

अब तक एजेंसियां विदेशियों को ब्लैक लिस्ट करती थीं। इसका कोई औचित्य नहीं था। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 कानून 36 धाराओं में है। इसमें पूरे प्रोसेस को कानूनी रूप दिया गया है। सारे एक्शन इसी हिसाब से होंगे। कोई विदेशी एयरपोर्ट या बंदरगाह की जगह कहीं और से आएगा तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा।

कठुआ एनकाउंटर- 3 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद

घायल डीएसपी एयरलिफ्ट; जैश के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली

कठुआ।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर जंगली इलाके में गुरुवार को दिनभर चली मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 3 जवान भी घायल हुए, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

तीन शहीद जवानों के नाम तारिक अहमद, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह हैं। इन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जम्मू-कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इन जवानों को पेट में गोली लगी थी।

एनकाउंटर में घायल डिप्टी एसपी धीरज सिंह समेत अन्य घायलों को उधमपुर भेजा गया है। सुरक्षाबलों ने बताया कि कठुआ जिले के राजबाग में गुरुवार सुबह करीब आठ बजे गोलीबारी शुरू हुई।

राजबाग के घाटी जुथाना इलाके के जखोले गांव में करीब 9 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट ने पुलिस पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने रात के लिए अभियान रोक दिया है, इसलिए अभी तक आतंकवादियों के शव बरामद नहीं किए जा सके हैं। शुक्रवार को सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा।

समान प्रश्न पत्र योजना एवं आरटीई पुर्नभरण की समस्याओं पर संघ का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव से मिला

प्रवेशित विद्यार्थियों की पुनर्भरण राशि का होगा भुगतान, सरकार नहीं करेगी अपील

निजी शिक्षण संस्थाओं की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा : कृष्ण कुणाल

एजेंसी

जयपुर। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ राजस्थान के अध्यक्ष डा. एल.सी. भारतीय के नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल से मिला।

महासचिव किशन मित्तल ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने समान परीक्षा शुल्क के साथ 10 रुपए अतिरिक्त लेने पर तत्काल रोक लगाने, आरटीई का पुनर्भरण तत्काल देने और उन्हें शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए ज्ञापन देते हुए कहा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग या अनुदान नहीं मिलता है और संस्थाएं अपने संसाधनों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग राज्य सरकार विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन से पूर्व मा. शि. बोर्ड द्वारा वार्षिक शुल्क की वसूली, आरटीई पुनर्भुगतान से पूर्व वार्षिक कटौती आदि नामों से तरह-तरह के शुल्क लगा कर निजी शिक्षण संस्थाओं से जबरन राशि वसूल करती है। इस वर्ष कक्षा 9 व 11 के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र देने से पूर्व रु. 10/- की अतिरिक्त जबरन वसूली कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से और की जा रही है।

महामंत्री किशन मित्तल ने शिक्षा सचिव को बताया कि आरटीई के अन्तर्गत पुनर्भरण की जाने वाली यूनिट कास्ट की राशि गत तीन सत्रों से रु. 13535/- फिक्स की हुई है

जबकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर प्रति विद्यार्थी व्यय की जा रही यूनिट कास्ट लगातार बढ़ रही है। PP3, PP4+, PP5+ में प्रवेशित विद्यार्थियों की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार सरकार निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही है।

मित्तल ने बताया कि निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक सत्र में निजी विद्यालयों को पुनर्भरण राशि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर व मार्च में दिये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने अधिनियम लागू होने के बाद एक सत्र में भी अधिनियम की पालना नहीं की है। इस वर्ष 2024-25 में पुनर्भरण के दावे बिल अभी तक राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किये हैं।

ज्ञापन के सभी बिन्दुओं पर वार्ता के बाद सहमति व्यक्त करते हुए शिक्षा सचिव ने समान प्रश्न पत्र योजना में अतिरिक्त शुल्क को अधिकारियों के साथ वार्ता कर समाप्त करने का आश्वासन दिया। यूनिट कास्ट 13535/- को बढ़ाने हेतु संघ के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया। PP3, PP4+, PP5+ में प्रवेशित विद्यार्थियों की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की और उनसे आग्रह करने पर उच्चतम न्यायलय में राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं करने का आश्वासन दिया और अगले सत्र से पुर्नभरण राशि के बिलों को समय पर किये जाने पर सहमति दी।

महामंत्री मित्तल ने बताया कि शिक्षा सचिव कुणाल ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ही संघ के प्रतिनिधियों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने का निर्णय लिया।

शिष्ट मंडल में संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीराम डंगायच एवं संस्था संचालक, शंकर लाल चौधरी, केशव राम अग्रवाल, राकेश कुमार शर्मा, राजाराम शर्मा, बैनी प्रसाद शर्मा सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

बीजेपी मंत्रियों को आवास पर जनसुनवाई के लिए पाबंध किया

जयपुर। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश कार्यालय में किस तरह से जनसुनवाई हो, इसे लेकर क्या तरीका अपनाया जाए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। हमने सभी मंत्रियों को पाबंध किया है कि वह अभी अपने आवास पर जनसुनवाई करें। इसके लिए सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनसुनवाई के लिए दिन व समय तय करें। इससे लोगों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जनसुनवाई करते हैं। वे जनता के बीच जाते है, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इसी तरह से अब मंत्रियों को भी अपने यहां जनसुनवाई के लिए पाबंध किया गया है।

खदान संचालकों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वैधता अवधि बढ़ाई

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 16 हजार खदान संचालकों को राहत देते हुए खनन की वैधता अवधि को दो माह के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह अवधि 31 मार्च तय थी। लेकिन प्रदेश में 23 हजार खदानों में से करीब खदान संचालकों को अभी तक राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में अंतरिम आवेदन दायर करके अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल, इस मामले में राजस्थान सरकार को तब झटका लगा, जब एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से समय सीमा बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध को अस्विकार कर दिया था।

रीट पेपरलीक मामला : सरकार ने गहलोत-राज की जांच सही मानी

कोर्ट में कहा- किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं

एजेंसी

जयपुर। भजनलाल सरकार ने में रीट भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गहलोत राज में हुई एसओजी कार्रवाई पर मुहर लगा दी। रीट भर्ती को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली पर भी पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान एएजी विज्ञान शाह ने कहा- रीट भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था, उसे सरकार ने रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवा ली थी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। ऐसे में इस मामले में किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने एबीवीपी और अन्य की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया।

गहलोत सरकार ने रद्द किया था पेपर

गहलोत सरकार ने साल 2020 में रीट भर्ती परीक्षा 2021 का विज्ञापन निकाला था। 26 सितंबर 2021 को एग्जाम हुआ था। एग्जाम के दिन ही परीक्षा का पेपर वॉट्सऐप पर लीक हो गया था। इसे लेकर पहली एफआईआर 27 सितंबर को गंगापुर सिटी थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद जयपुर के सिंधी कैंप, मुहाना मंडी और श्याम नगर थाने में भी पेपर लीक को लेकर मामला दर्ज हुआ था। मामला बढ़ने पर उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने पेपर रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट में भी एबीवीपी सहित कई याचिकाएं दायर हुई थी। गहलोत सरकार ने 7 फरवरी 2022 को इस भर्ती परीक्षा के रीट लेवल-2 के पेपर को रद्द कर दिया था।

जम्मू के कठुआ में सेना-आतंकियों के बीच एनकाउंटर , 2 आतंकी मारे गए

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार सुबह से जारी मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। तीन आतंकियों की तलाश जारी है। डीएसपी धीरज सिंह समेत पांच सुरक्षाकर्मी घायल हुये। सभी को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जुठाना इलाके में 4-5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, इस दौरान फायरिंग शुरू हो गई। इससे पहले सोमवार को कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तब आतंकियों ने एक बच्ची और उसके माता-पिता को पकड़ लिया था। मौका मिलने पर तीनों आतंकियों के चंगुल से भाग निकले थे। इस दौरान बच्ची की मामूली चोटें आई थीं।

सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर वार, कहा-

'गरीबी हटाओ' सिर्फ नारा था, काम हमने किया : भजनलाल

एजेंसी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह के मंच से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक 'गरीबी हटाओ' सिर्फ एक नारा था। असली काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।

राजस्थान दिवस अब भारतीय नववर्ष पर: अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय कल्याण योजना हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि राजस्थान का एकीकरण जिन परिस्थितियों में हुआ था, वही रेवती नक्षत्र और इंद्र योग इस बार भी बन रहा है। इस ऐतिहासिक संयोग को देखते हुए उन्होंने घोषणा की कि अब से राजस्थान दिवस 30 मार्च के बजाय भारतीय नववर्ष, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाया जाएगा।

निवेश और रोजगार पर जोर: मुख्यमंत्री ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य में अब तक 35 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। खास बात यह है कि पहली तिमाही में ही 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक 60000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप चुकी है। 30 मार्च को और नियुक्तियां दी जाएंगी।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ट्वीट करने में व्यस्त थी, जबकि हम जमीन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक घोटाले चरम पर थे, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री होटलों में बैठकर सत्ता बचाने की राजनीति कर रहे थे। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जिले के सभी विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

गरीबों और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने गरीब महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कोई भूखा न रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने बीपीएल मुक्त गांव योजना की शुरुआत की घोषणा की। पहले चरण में 5000 गांवों को बीपीएल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा, मेवात और बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ और बृज क्षेत्र विकास बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की घोषणा की।

युवाओं, मजदूरों और उद्यमियों के लिए राहत

- **2 लाख** परिवारों को ड्रोन सर्वे के आधार पर पट्टे वितरित किए जाएंगे, जिसमें से 20 हजार परिवारों को आज पट्टे सौंपे गए।
- **311 लोगों** को डेयरी बूथ आवंटित किए गए।
- **उद्योगपतियों** को भी पूरी बिजली आपूर्ति का आश्वासन
- **2000** इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन वितरित की जाएंगी।
- **ट्रक-बस** ड्राइवरों और श्रमिकों के लिए 'मां नेत्र वाउचर योजना' के तहत निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **मुफ्त** बिजली योजना के तहत अब 150 यूनिट तक बिजली निशुल्क दी जाएगी।
- **2027 तक** प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

रोकना होगा राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को

रमेश सर्राफ धमोरा

एक समय था जब धरातल पर काम करने वाला पार्टी कार्यकर्ता आगे चलकर जनप्रतिनिधि बनता था। जमीन से उठकर आगे आने वाला नेता आम जनता से जुड़ा रहता था और वह जनता के सुख-दुख से वाकिफ भी होता था। इसलिए वह आमजन के हित में काम करता था। मगर अब लोग पैसे के बल पर पैराशूट से उतरकर राजनीति करने लगे हैं। वह पैसे के बल पर ही चुनाव जीत जाते हैं।

हमारे देश के राजनेताओं में दिन-प्रतिदिन नैतिकता कम होती जा रही है। कई बड़े नेता आए दिन विवादास्पद बयान देखकर चचाओं में बने रहते हैं। वहीं बहुत से निर्वाचित विधायकों, सांसदों, मंत्रियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर अपराधिक मामले दर्ज हो रहें हैं। जिससे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों की छवि खराब होती जा रही है। देश की राजनीति में आज अपराध का इतना घालमेल हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा जनप्रतिनिधि अपराधी है और किसकी छवि स्वच्छ है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के नेता बनने से जहां राजनीतिक दागदार हुई है। वहीं नेताओं की जनता की दूरी भी बढ़ने लगी है। मौजूदा समय में राजनीतिक व्यवसाय बन चुकी है। राजनीति में वही लोग सफल होते हैं जो या तो बड़े नेताओं के परिवार से है या फिर बहुत पैसे वाले हैं। राजनीति के क्षेत्र में अब सेवा, संगठन, वफादार कार्यकताओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। राजनीति पूरी तरह पैसों की चकाचौंध में लिप्त हो गई है।

एक समय था जब धरातल पर काम करने वाला पार्टी कार्यकर्ता आगे चलकर जनप्रतिनिधि बनता था। जमीन से उठकर आगे आने वाला नेता आम जनता से जुड़ा रहता था और वह जनता के सुख-दुख से वाकिफ भी होता था। इसलिए वह आमजन के हित में काम करता था। मगर अब लोग पैसे के बल पर पैराशूट से उतरकर राजनीति करने लगे हैं। वह पैसे के बल पर ही चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए उन्हें आमजन की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं रहता है। ऐसे नेता पांच सितारा संस्कृति के वाहक होते हैं। ऐसे नेता राजनीति में आने के लिए पहले खूब पैसा खर्च करते हैं और जब किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो जमकर भ्रष्टाचार कर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही आज राजनीति समाज सेवा की बजाय व्यवसाय बन गई है।

1971 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू सीट पर देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के कृष्ण कुमार बिड़ला को हराने वाले शिवनाथ सिंह गिल को मैंने 1998 से 2003 में विधायक के रूप में देखा है। वह अपने क्षेत्र से जयपुर जाते या अपने घर से विधानसभा जाते हमेशा सरकारी बस का ही उपयोग करते थे। कभी निजी गाड़ियों से नहीं घूमते थे। इसी के चलते उन्होंने राजनीति में 50 साल लंबी पारी खेली थी। वह ईमानदार थे इसीलिए ईमानदारी से रहते थे। आज हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी कई लाख रूपयों की महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। पार्टी का कोई नेता उनसे यह नहीं पूछता है कि इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे कहां से आता है। सबको पता है की राजनीति में आज छूट-भैया नेता भी सत्ता की दलाली में पैसा कमा रहे हैं। दलाली के पैसों में बड़े नेताओं का भी हिस्सा होता है। इसीलिए उनकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठाता हैं।

चुनाव सुधार पर काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 45 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संगठन ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया है। जिसमें आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 यानी 79 प्रतिशत विधायकों ने जबकि सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक 3 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 यानि 86 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उक्त रिपोर्ट से पता चला कि 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें 1205 पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट के अनुसार 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। वहीं 226 पर धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं। इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें 13 पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 और 376 (2)(द) के तहत बलात्कार का आरोप है। धारा 376 (2)(द) एक ही पीड़ित के बार-बार यौन उत्पीड़न से संबंधित है।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 (46 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें से 27 को दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में चुने जाने वाले आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कुल 233 सांसदों (43 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। जबकि 2014 में 185 (34 प्रतिशत), 2009 में 162 (30 प्रतिशत) और 2004 में 125 (23 प्रतिशत) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2024 में लोकसभा के लिये चुने गये 251 उम्मीदवारों में से 170 (31 प्रतिशत) पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण से पता चला कि यह 2019 में 159 (29 प्रतिशत) सांसदों, 2014 में 112 (21 प्रतिशत) सांसदों और 2009 में 76 (14 प्रतिशत) सांसदों की तुलना में भी वृद्धि है।

एडीआर के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 (39 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49 (49 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं और समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 21 (45 प्रतिशत) पर आपराधिक आरोप हैं। विश्लेषण में पाया गया कि 63 (26 प्रतिशत) बीजेपी उम्मीदवार, 32 (32 प्रतिशत) कांग्रेस उम्मीदवार और 17 (46 प्रतिशत) समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें कहा गया है कि सात (24 प्रतिशत) टीएमसी उम्मीदवार, छह (27 प्रतिशत) डीएमके उम्मीदवार, पांच (31 प्रतिशत) टीडीपी उम्मीदवार और चार (57 प्रतिशत) शिवसेना उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार केरल के 20 में से 19 (95 प्रतिशत) सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से 11 गंभीर अपराधों से जुड़े हैं। तेलंगाना के 17 में से 14 (82 प्रतिशत), ओडिशा के 21 में से 16 (76 प्रतिशत), झारखंड के 14 में से 10 (71 प्रतिशत) और तमिलनाडु के 39 में से 26 (67 प्रतिशत) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर हरियाणा 10 और छत्तीसगढ़ 11 सांसद में केवल एक-एक सांसद पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के 13 में से 2, असम के 14 में से 3, दिल्ली के 7 में से 3, राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात के 25 में से 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित हैं।

एक जनवरी 2025 तक वर्तमान या पूर्व विधायकों के खिलाफ कुल 4,732 आपराधिक मामले लंबित थे। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1,171 मामले दर्ज हैं। ओडिशा (457), बिहार (448), महाराष्ट्र (442), मध्य प्रदेश (326), केरल (315), तेलंगाना (313), कर्नाटक (255), तमिलनाडु (220), झारखंड (133) और दिल्ली (124) मुकदमे लंबित हैं।

उपरोक्त आंकड़ों को देखने से लगता है कि हमारे देश की राजनीति में आपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश के लिए एक बड़ा नासूर बन जाएगी। एक समय ऐसा होगा जब राजनीति का पूरी तरह अपराधीकरण हो जाएगा और स्वच्छ छवि के लोग राजनीति से दूर होते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। सरकार को भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे तभी राजनीति में बढ़ती अपराधियों की संख्या पर लगाम लग पाएगी।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

भारत और पीओके

केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार की कश्मीर नीति अपनी गति पर है। इसका एक उदाहरण मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर दिखाई दिया जब भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो उसे खाली करना होगा। पाकिस्तान किसी न किसी बहाने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसने कश्मीर का मुद्दा फिर उठाया था जिसका भारतीय प्रतिनिधि ने कड़े. शब्दों में जवाब दिया। पार्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान समेत विश्व बिरादरी को 22 फरवरी, 1994 को भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव की याद दिलाई जिसमें यह दोहराया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। वास्तव में भारतीय प्रतिनिधि हरीश की यह टिप्पणी संसद के इसी प्रस्ताव की प्रतिध्वनि है। कुछदिन पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान जम्मू-कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के निवासी पाकिस्तानी सरकार के शोषण और जुल्म से परेशान हैं और पीओके का भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके और यहां के निवासियों को गुलाम बना रखा है। यहां के संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के लोगों के लिए किया जा रहा है। सेना और पुलिस बल का जुल्म बढ़ख्ता जा रहा है। यहां के लोग शोषण और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आंदोलनरत हैं। वास्तविकता यह है कि पीओके पाकिस्तान के बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है। वहां असंतोष की आग लगी हुई है। शायद ही कोई दिन जाता हो जब पाकिस्तान सरकार और यहां की प्रांतीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न होते हों। और हर बार पुलिस और सेना उनका बर्बरता से दमन करती हैं। यहां के कश्मीरी अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि पीओके का भविष्य अस्थिर, अराजकताग्रस्त और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त पाकिस्तान जैसे देश के साथ नहीं, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक, स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत देश के साथ है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके को भारत में वापस लाने के लिए नई दिल्ली को वैश्विक समर्थन जुटाना होगा।

चिंतन-मनन

हनुमान से सीखें संस्कार

दूसरे का मान रखते हुए हम सम्मान अर्जित कर लें, इसमें गहरी समझ की जरूरत है। होता यह है कि जब हम अपनी सफलता, सम्मान या प्रतिष्ठा की यात्रा पर होते हैं, उस समय हम इसके बीच में आने वाले हर व्यक्ति को अपना शत्रु ही मानते हैं। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मनुष्य सारे संबंध दांव पर लगा देता है। आज के युग में महत्वाकांक्षी व्यक्ति का न कोई मित्र होता है, न कोई शत्रु। उसे तो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी होती है। हर संबंध उसके लिए शस्त्र की तरह हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरे की भावनाओं, रिश्ते की गरिमा और सबके मान-सम्मान को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा पर चलते हैं। हनुमानजी उनमें से एक हैं। सुंदरकांड में एक प्रसंग है। हनुमानजी और मेघनाद का युद्ध हो रहा था। मेघनाद बार-बार हनुमानजी पर प्रहार कर रहा था, लेकिन उसका नियंत्रण बन नहीं रहा था। तब उसने हनुमानजी पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। हनुमानजी को भी वरदान था कि वह किसी अस्त्र-शस्त्र से पराजित नहीं होंगे। उनका नाम बजरंगी इसीलिए है कि वे वज्रांग हैं। जिसे कह सकते हैं स्टील बॉडी।

जैसे ही शस्त्र चला, हनुमानजी ने विचार किया और तुलसीदासजी ने लिखा -

ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा कपि मन कीन्ह बिचार।
जौं न ब्रह्मसर मानउं महिमा मिटइ अपार।।

अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब हनुमानजी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। यहां हनुमानजी ने अपने पराप्रम का ध्यान न रखते हुए, ब्रह्मजी के मान को टिकाया। दूसरों का सम्मान बचाते हुए अपना कार्य करना कोई हनुमानजी से सीखें।

'कुआँ सूखने पर ही पता चलता है पानी की कीमत'

डॉ. सत्यवान सौरभ

एक सुदूर घाटी में बसे गांव में एक झरना था जिसे जीवन धारा कहा जाता था। पीढ़ियों तक ग्रामीणों ने इसका उपयोग किया, लेकिन जब आधुनिक सुविधाएं आईं, तो यह उपेक्षित हो गया। एक साल, भीषण सूखे ने झरने को सुखा दिया, और तभी ग्रामीणों को इसकी कीमत का एहसास हुआ। यह कहानी दशार्ती है कि हम अक्सर किसी चीज के महत्व को तब तक नहीं समझते जब तक वह खत्म नहीं हो जाती। पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, संबंध और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये हमेशा बने रहेंगे, परंतु जब यह संकट में होते हैं, तभी हम उनकी कीमत समझते हैं। जीवन की क्षणभंगुरता हमें वर्तमान का आदर करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे नल से पानी की सतत आपूर्ति को हम सामान्य मानते हैं, वैसे ही हम अपनों, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को भी हल्के में लेते हैं।

जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो हम उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं। अरस्तू के नैतिक दर्शन के अनुसार, जागरूकता और संतुलन ही सच्चे गुणों को जन्म देते हैं। भरे कुएं का पानी हमें कृतज्ञ नहीं बनाता, परंतु पानी की कमी हमें उसकी महत्ता सिखाती है।

1930 के दशक की महामंदी ने लोगों को यह समझाया कि संसाधनों की उपलब्धता और कमी का चक्र कैसा होता है। ग्रीक त्रासदियों में अक्सर चरित्रों को जीवन का सच्चा अर्थ तब पता चलता है जब वे सब कुछ खो चुके होते हैं। शेक्सपियर के किंग लियर को प्यार की वास्तविकता तब समझ आई जब वह धोखा खा चुका था। महामारी ने भी हमें सामाजिक मेलजोल की अहमियत सिखाई। मानवता बार-बार संसाधनों का दुरुपयोग करती है और फिर संकट के समय उन्हें बचाने का प्रयास करती है। नीत्शे की शाश्वत पुनरावृत्ति की अवधारणा बताती है कि जब तक हम सच में नहीं सीखते, हम वही गलतियाँ दोहराते हैं। 1930 के डस्ट बाउल संकट ने कृषि को नुकसान पहुँचाया, जिससे सबक लेकर सुधार हुए, लेकिन समय के साथ लोग फिर लापरवाह हो गए।

उपयोगितावादी दर्शन कहता है कि किसी चीज का मूल्य उसकी उपयोगिता से निर्धारित होता है। जल की वास्तविक कीमत उसकी उपलब्धता के अनुसार बदलती है। उप-सहारा अफ्रीका में पानी की कमी ने जल संरक्षण के नए समाधान उत्पन्न किए। इसी तरह, जब कोई संसाधन दुर्लभ हो जाता है, तब उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जल संकट सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। पारिस्थितिक दर्शन बताता है कि हमें प्रकृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। अरल सागर का सूखना इसका उदाहरण है, जिससे सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हुए। यदि हम संसाधनों को संरक्षित नहीं करते, तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। धार्मिक और दार्शनिक परंपराएँ बताती हैं कि वंचना मूल्य की गहरी समझ देती है। रमजान के उपवास लोगों को भोजन की कीमत और जरूरतमंदों की स्थिति का एहसास कराते हैं। इसी तरह, कठिनाइयाँ हमें जीवन की असली जरूरतों का महत्व सिखाती हैं।

मानव अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, और जल संकट इस निर्भरता को दशार्ता है। फुकुशिमा परमाणु आपदा ने भी दिखाया कि तकनीकी विकास के बावजूद हम प्राकृतिक शक्तियों के आगे असहाय हैं। यह हमें हमारे संसाधनों की सीमाओं का सम्मान करना सिखाता है। पानी जीवन देता है, परंतु बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं से विनाश भी ला सकता है। ताओवाद के अनुसार, जीवन विरोधाभासों से भरा है, और हमें संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों में जल को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में बपतिस्मा का जल आत्मा की पुनर्जन्म का संकेत देता है। कुँए का सूखना हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, 'पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती।' भारत में चिपको आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि समुदाय मिलकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकता है।

कहावत ₹जब तक कुआँ सूख नहीं जाता, हमें पानी की कीमत का पता नहीं चलता₹ एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। हमें संसाधनों के खत्म होने से पहले उनके महत्व को समझना चाहिए। जल, प्रेम, स्वास्थ्य या स्वतंत्रता–इन सभी को खोने से पहले संजोना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण हो सके। पानी सिर्फ एक भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं–स्वास्थ्य, रिश्ते और स्वतंत्रता–का प्रतीक भी है। जब ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो हम उन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वे खतरे में होते हैं या खो जाते हैं, तब हमें उनका महत्व समझ आता है।

मनीष कुमार चौधरी

यूरोपीय संसद के एक खंसीसी सदस्य ने हाल में एक पार्टी मीटिंग में मजाक करते हुए कहा, 'हम उन अमेरिकियों से कहने जा रहे हैं जिन्होंने अत्याचारियों का साथ देने का फैसला किया है, उन अमेरिकियों से जिन्होंने वैज्ञानिक स्वतंत्रता की मांग करने के लिए शोधकताओं को निकाल दिया, हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वापस दे दो।' भले ही यह टिप्पणी हल्के-फुल्के अंदाज में कही गई हो, पर इसके मायने गंभीर हैं। अमेरिका को यह मूर्ति उपहार में देने वाले देश के एक अधिकारी ने इसे वापस मांगा है, यह इस बात का संकेत है कि 'ब्रांड अमेरिका' अपनी साख खो रहा है। बहिष्कार, विरोध और सामान्य दुश्मनी के बीच, इराक युद्ध के दिनों के बाद से अब तक अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक अलोकप्रिय हो सकता है।

इन दिनों ट्रंप किसी शक्तिशाली देश के प्रमुख से ज्यादा घाघ व्यापारी की तरह नजर आ रहे हैं, जो फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बार-बार

राज्यपाल रमेन डेका के हाथों शिवराम को मिली 'आशियाने' की चाबी घर पहुंचकर राज्यपाल ने सौंपा अभिनन्दन पत्र

भावुक मन से शिवराम ने कहा, 'कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा'

मरुधर विशेष

करन सोनी कोरिया। खुशियों के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और मेहनत से निभाना होता है। मेहनतकश लोगों के लिए अवसर अपने आप आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ ग्राम जूनापारा निवासी शिवराम के साथ हुआ, जब उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें प्रदेश के राज्यपाल से मिलने और उनके हाथों अपने घर की चाबी लेने का अवसर मिलेगा।

राज्यपाल ने सौंपा अभिनंदन पत्र

शिवराम पेशे से एक राजमिस्त्री हैं और वर्षों से दूसरों के पक्के मकान बनाते आ रहे हैं। लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिला, तो उन्होंने महज तीन महीनों में अपना खुद का मकान तैयार कर लिया। उनके इसी परिश्रम और उपलब्धि की सराहना करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने उनके नवनिर्मित आवास पर जाकर उन्हें अभिनंदन पत्र सौंपा और शुभकामनाएँ दीं।

राज्यपाल के आगमन से गदगद हुए शिवराम

राज्यपाल रमेन डेका अपने एक दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत जूनापारा पहुँचे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने हितग्राही शिवराम के नवनिर्मित आवास का अवलोकन किया और उनके समर्पण की सराहना की।

जीवन का सबसे यादगार पल

भावुक शिवराम ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में राज्यपाल आएँगे और मुझे सम्मानित करेंगे। यह मेरे जीवन का सबसे यादगार पल है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले सहयोग के लिए सरकार का आभार प्रकट किया।

तीन माह में पूरा किया अपना सपना

शिवराम को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चुना गया। उन्हें इस योजना की पहली किस्त मिलते ही उन्होंने तेजी से काम शुरू किया और मात्र तीन महीनों में अपने सपनों का घर पूरा कर लिया। उनके इस मेहनत और लगन की सराहना जिला प्रशासन द्वारा भी की गई।

सरकार की योजना ने बदली जिंदगी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से अब तक हजारों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला है। राज्यपाल रमेन डेका ने भी इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक इस योजना का लाभ जल्द से जल्द पहुँचाया जाए।

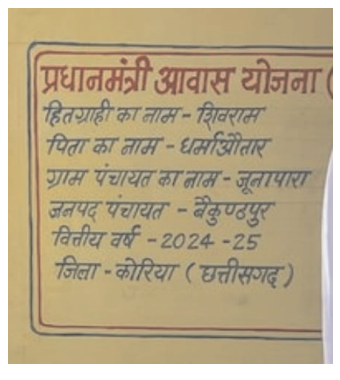

सोना तस्करी मामले में रन्या राव को झटका, जमानत याचिका फिर खारिज

बेंगलुरु (एजेंसी)। सोना तस्करी के आरोप के चलते जेल में बंद कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव को बड़ा झटका लगा है। 64वें सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट (सीसीएच) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले आर्थिक अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुका था। जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद अब उनके पास हाईकोर्ट का विकल्प बचा है और उनका कानूनी दल जल्द ही वहां अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी अनुसार न्यायालय ने अनेक बिंदुओं को सामने रखते हुए रन्या राव की जमानत अर्जी को खारिज किया है। ऐसे ही कई गंभीर बिंदुओं में अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से कनेक्शन प्रमुख है। जांच में सामने आया है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है। इसके साथ ही कस्टम नियमों का उल्लंघन है। हवाई यात्रा के दौरान उन्होंने कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन किया। जांच एजेंसियों ने दलील दी कि जमानत मिलने पर रन्या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। उनकी विदेश यात्राएं भी संदिग्ध बताई गई हैं। एक साल में 27 बार विदेश यात्रा करने के कारण उनकी गतिविधियां शक के दायरे में हैं। ऐसे में कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।

कैलास मानसरोवर, और ओम पर्वत दर्शन यात्रा की तैयारी शुरु

पिथौरागढ़ । कैलास मानसरोवर, आदि कैलास और ओम पर्वत दर्शन यात्रा 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यात्रा को लेकर बुधवार को सेना और प्रशासन के बीच बैठक हुई। बैठक में इस यात्रा को सुगम बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, स्थानीय सेना के ब्रिगेडियर गौतम पठानिया, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। उच्च हिमालय में सुरक्षा की व्यवस्था सेना के हाथों में हैं। आदि कैलास और ओम पर्वत इसी क्षेत्र में आते हैं। कैलास मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी उच्च हिमालय से ही है। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि मसलों पर भारतीय सेना प्रशासन को सहयोग देती है। बैठक में मौजूद ब्रिगेडियर पठानिया ने यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताकर कहा कि उच्च हिमालय में यात्रा के संचालन में सेना पूरी मदद देगी। जिलाधिकारी गोस्वामी ने कहा कि यात्रा के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में जिले में पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने पर भी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। वहीं कोरोना काल से बंद पड़ी कैलास मानसरोवर यात्रा शुरू होने को लेकर स्थानीय लोग गदगद हैं। भारत और चीन के बीच पिछले दिनों कई स्तरों की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 में कैलास मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगी। इससे स्थानीय लोग खुश हैं। यात्रा सीजन में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने है।

मुंबई पुलिस ने अवैध रुप से रह रहे आठ बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया

-पुलिस से बचने के लिए यह किन्नर बनकर रहते

मुंबई (एजेंसी)। देश के अलग-अलग हिस्सों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने पहली बार आठ बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह सभी बांग्लादेशी हैं, और लिंग बदलकर रहते थे। मुंबई पुलिस शहर में बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस से बचने के लिए यह किन्नर बनकर रहते थे। ये सभी नागरिक मुंबई में करीब पांच साल से रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी कलाकार (नृत्य कलाकार) के रूप में काम करते थे और वैध दस्तावेजों के बिना मुंबई में रह रहे थे। इन आरोपियों ने अपने नाम, पहचान और कुछ मामलों में अपना लिंग भी बदल लिया था, जिससे वे अन्य नागरिकों से अलग दिखते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रफीक नगर इलाके में जाल बिछाकर आठ ट्रांसजेंडर बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि इन सभी ने बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। गिरफ्तार आरोपी वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी और ग्राहकों को ठगने और लूटने के मामलों में भी शामिल थे। मुंबई में पहली बार हुआ है जब ट्रांसजेंडर के रूप में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच में पाया कि ये सभी पुरुष है और अपनी पहचान छुपाने के लिए ट्रांसजेंडर बन कर रहते थे। इसके पहले 26 मार्च को पुलिस की टीम ने गोवंडी और चेंबूर इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इसमें पांच महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने अवैध घुसपैठियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। हर टीम को एक निश्चित क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जहां उन्होंने गहन जांच-पड़ताल कर अवैध रूप से भारत में रह रहे इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था।

बिहार के मंदिर प्रांगण में कन्हैया कुमार ने की आमसभा तो युवाओं ने गंगाजल से धोया

सहरसा (एजेंसी)। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको पदयात्रा में बिहार के सहरसा जिले के बनगांव में विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने मंगलवार रात बनगांव स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में नुक्कड़ सभा की थी, जिसे लेकर स्थानीय युवाओं ने विरोध किया था । बुधवार को कुछ युवाओं ने मंदिर प्रांगण को गंगाजल से धोने की कार्रवाई की। विरोध कर रहे युवाओं का कहना था कि कन्हैया कुमार पर पहले देशद्रोह का आरोप लग चुका है और उनके कथित विवादित बयानों को देखते हुए मंदिर परिसर में उनका भाषण देना अनुचित था। हालांकि स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार का पारंपरिक पाग, चादर और माला पहनाकर स्वागत किया था, लेकिन अगले ही दिन युवाओं द्वारा की गई इस प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई ने क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है।

-महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले- बीजेपी का दोहरा रवैया उजागर

पहले बंटेंगे तो कटेंगे का दिया नारा अब सौगात-ए-मोदी किट बांट रहे

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद पर सौगात-ए-मोदी किट बांटने की योजना पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी का दोहरा रवैया उजागर हो गया है। यह सौगात-ए-मोदी नहीं है बल्कि सौगात-ए-सत्ता है। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी एक्सपोज हो रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो इन लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और अब सौगात-ए-मोदी वाली किट बांट रहे हैं। आखिर यह कैसी किट है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ को साधने वाली यह किट है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह योजना बीजेपी ने बिहार चुनाव में फायदा उठाने के लिए बनाई है। बीजेपी तो मुझ पर आरोप लगाती रही है कि मैंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, अब वही बताएं कि क्या कर रही है। उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा के मामले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार कामरा को गद्दारों के अपमान पर समन जारी कर रही है, लेकिन इस सरकार ने अब तक राहुल सोलापुरकर के मसले पर कुछ नहीं कहा, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। बता दें कि बुधवार को ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा था और कहा था कि शिवसेना मालिक और गुलामों की नहीं बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है।

शिवसेना (यूबीटी) से शिवसेना में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि उनके जैसे सैनिक सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि हमने लोगों के जीवन में सुनहरे दिन लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और मैं आपका सहयोगी हूं। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि मालिक और गुलामों की पार्टी।' शिंदे ने कहा कि उन्होंने हमेशा आलोचना और दुर्व्यवहार का जवाब अपने काम से दिया है।

वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने वाले अब दौरा करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वे होली के नाम पर पूरे साल मुसलमानों के नाम पर घृणा फैलाएंगे और फिर चुनाव आने पर उन्हें लुभाएंगे। ठाकरे ने बीजेपी की आलोचना करते

हुए कहा कि इससे पहले कि आप हम पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाएं, आपको अपने झंडे से हरा रंग हटा देना चाहिए। अब उनका पाखंड उजागर हो गया है। ठाकरे ने कहा कि वे हरा रंग नहीं हटाएंगे। आपने चुनाव से पहले कई वादे किए थे। बिजली बिल माफी, कर्ज माफी, लड़की बहिन योजना का क्या हुआ?

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री बैरवा को जेल से मिली धमकी, विपक्ष ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल

जयपुर। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी भरा कॉल जयपुर सेंट्रल जेल से आया। जेल से इस तरह का कॉल आना बेहद गंभीर मुद्दा है। इस घटना के बाद जयपुर पुलिस भी एक्शन में आ गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि धमकी भरा कॉल आया है। इसके बाद प्रशासन सख्त है और जांच में जुटा है। इस धमकी के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है।

घटना के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने इस धमकी भरे कॉल को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस मामले पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि उपमुख्यमंत्री को जब धमकी भरा फोन आ सकता है तो इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संदेह पैदा होता है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि जयपुर सेंट्रल जेल से प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिलना चिंताजनक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल के बाद आज उपमुख्यमंत्री को सेंट्रल जेल से धमकी मिलना प्रदेश की वास्तविक कानून व्यवस्था का एक आईना है। प्रदेश में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को ही जेल से धमकियां मिल रही हैं वो ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा? मुख्यमंत्री मामला बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है, प्रदेश में अपराधी बेख़ौफ़ हैं मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेकर प्रकरण की गहराई से जांच की जाए आखिर अपराधियों के पास जेलों में मोबाइल कैसे पहुंच रहे है?

शहर की सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दे: आयुक्त नगर निगम चिरमिरी

मरुधर विशेष, करन सोनी

एमसीबी। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के निर्देशानुसार नगर निगम के महापौर रामनरेश राय के मार्गदर्शन में प्रतिदिन की भांति गुरूवार की सुबह भी नगर निगम के आयुक्त रामप्रसाद आचला ने नगर के पोड़ी बड़ानाला, कोरिया एवं गेल्हापानी के एस.एल.आर.एम. सेन्टर व कोरिया में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयुक्त आचला ने भ्रमण के दौरान एस.एल.आर.एम. सेन्टर का अवलोकन कर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वच्छता दीदीयों द्वारा सेंटर परिसर में संपादित कार्यो का विस्तार से जानकारी प्राप्त की। वहीं कोरिया कॉलरी में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्यो की गुणवत्ता को देखा और संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्य की गुणवत्ता और वर्क क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखते हुए समय-सीमा के भीतर कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक रामगोपाल मलिक व निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहें।

अब कॉमेडियन कामरा ने पीएम मोदी को तानाशाह कहकर उड़ाया मजाक

-विपक्ष ने बीजेपी की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा-पैरोडी गाने पर तो भड़क गए थे

मुंबई (एजेंसी)। अभी एकनाथ शिंदे पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि मुंबई के खार में हाल ही के स्टैंड-अप सेट में कुणाल कामरा ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मज़ाक उड़ा दिया। उन्होंने संगीत के ज़रिए पीएम मोदी को तानाशाह और दोगला बताया। कामरा ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करने के लिए फिल्म बादशाह के मशहूर गाने बादशाह ओ बादशाह को फिर से गाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मज़ाक उड़ाने के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है और शिवसेना ने उनके खिलाफ धमकियां दी हैं। शिवसेना ने उस जगह पर भी तोड़फोड़ की है जहां कॉमेडियन कामरा ने परफॉर्म किया था।

विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कुणाल कामरा के मजाक पर बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, जबकि उनके पैरोडी गाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए स्टैंड-अप कॉमेडियन को दूसरा समन जारी किया है। कॉमेडियन कामरा को शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर दर्ज मामले में उपनगरीय मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है।

पुलिस ने कुणाल कामरा को पहला समन जारी किया था, जिसमें उनके खिलाफ मानहानि मामले की जांच शुरू होने पर उनकी उपस्थिति मांगी गई। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नोटिस मिलने के बाद कामरा ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि बीजेपी कुणाल कामरा द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे कटाक्ष करने पर चुप रही, लेकिन उनके पैरोडी गाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया गया था। दानवे ने कहा कि कुणाल कामरा ने अपने शो में सीधे पीएम मोदी की आलोचना की, और बीजेपी ने कोई बुरा नहीं माना, लेकिन वही पार्टी एक पैरोडी गाने पर भड़क गई, जिसमें शिंदे का नाम भी नहीं था। ऐसा लगता है कि बीजेपी कामरा को निशाना बनाने के लिए शिंदे का इस्तेमाल कर रही है।

एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना, कामरा ने उपमुख्यमंत्री पर उनके राजनीतिक करियर को लेकर निशाना साधा, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ 2022 का विद्रोह भी शामिल है, जिसके कारण

महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी। उन्होंने दिल तो पागल है के एक लोकप्रिय हिंदी गाने की पैरोडी की, जिसमें शिंदे को गद्दार बताया था। कामरा ने महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी मज़ाक उड़ाया, जिसमें 2022 में शिवसेना और 2023 में एनसीपी में विभाजन शामिल है।

मेरठ में सड़कों पर ईद की नमाज की मानही, केंद्रीय मंत्री चौधरी ने आलोचना की

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने सड़कों पर ईद की नमाज को लेकर सख्त कदम उठाकर आदेश जारी किया है। पुलिस ने सार्वजनिक जगहों और सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है। मेरठ पुलिस के आदेश की केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये कहना गलत है। नमाजियों पर मेरठ पुलिस की कार्रवाई पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा, मेरा मतलब है, पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए कि हम पासपोर्ट ले लेने वाले है। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों से संवाद करना चाहिए। बता दें कि मेरठ पुलिस ने कहा कि इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करते मिला तब उसके खिलाफ कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही पासपोर्ट व लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की जाएगी। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि ईद पर सभी धर्मगुरुओं और इमामों से अपील की गई है कि लोग मस्जिदों या ईदगाहों में ही नमाज अदा करें।

जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए भर्ती हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू 04 अप्रैल को

मरुधर विशेष, करन सोनी

एमसीबी। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु संविदा पदों की भर्ती की जा रही है। भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के तहत "मिशन शक्ति" की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनरूप जिला स्तरीय हब हेतु जिले में 07 स्वीकृत संविदा पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को परीक्षण/मूल्यांकन उपरांत पात्र-अपात्र सूची का प्रकाशन उपरांत पात्र उम्मीदवारों का वाक इंटरव्यू कौशल परीक्षा 04 अप्रैल 2025 को समय 11:00 बजे प्रातः से स्थान सेंट पैट्रिक अकेडमी स्कूल लालपुर, चौघड़ा मनेन्द्रगढ़ जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर में आयोजित किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति एवं परिचय पत्र साथ ही पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि) भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। इसके साथ ही जिले के वेबसाईट 222.manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in व कार्यालय के सूचना पटल पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जशपुर का स्वास्थ्य मिशनः सीमावर्ती ग्रामीणों के लिए वरदान बना लोदाम सीएचसी, झारखंड के मरीजों को भी मिल रही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ, आयुष्मान कार्ड से हो रहा निःशुल्क उपचार

लोदाम सीएचसी पिछले एक साल में 62 झारखंड राज्य के निवासियों की हुई सामान्य प्रसव

मरुधर विशेष, करन सोनी

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के हो रहे विस्तार का लाभ पड़ोसी राज्य झारखंड को भी मिल रहा है। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर जशपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लोदाम झारखंड बॉर्डर के समीप है। यहां पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोदाम में झारखंड के आसपास के गावों के लोग अपना इलाज कराने आते हैं। इसके साथ ही उनका आयुष्मान कार्ड भी यहां पर बन रहा है।

लोदाम सीएचसी की बीपीएम इसमहिमा तिग्गा के अनुसार झारखंड के मांझा टोली, रायडीह, तुरुमा सहित अन्य ग्राम पंचायतों के लोग यहां की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इलाज के लिए आते हैं। पिछले 01 साल में यहां 62 झारखंड निवासियों की सामान्य प्रसव सफलतापूर्वक कराई गई है। इसके साथ ही 58 टाइफाइड मरीजों का उपचार किया गया है। इसके अलावा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग यहां आते हैं। लोदाम सीएचसी में एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सामान्य प्रसव, आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं सहित अन्य बीमारियों के इलाज की भी सुविधा है।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। इसी के तहत इस बार के बजट में कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही इस बजट में जशपुर में नवीन शासकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलने का निर्णय, जशपुर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

नारी और पानी का अद्भुत संयोग-जल संरक्षण की दिशा में कोरिया प्रशासन का नवाचार

'आवा पानी झोंकी' अभियान से मिलेगा जल संरक्षण को बढ़ावा

कल दो ग्राम पंचायतों में जल बचाने के लिए होगा जन चौपाल का आयोजन

मरुधर विशेष

करन सोनी कोरिया। जल संरक्षण को लेकर देशभर में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। गिरते भूजल स्तर की चुनौती से निपटने के लिए आम जनता से लेकर शासन-प्रशासन तक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी दिशा में कोरिया जिला प्रशासन ने एक नवाचार करते हुए 'आवा पानी झोंकी' अभियान शुरू किया है, जिसका अर्थ है आओ सब मिलकर पानी को रोके। इस अभियान के तहत जल संरक्षण में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

नारी शक्ति से जल शक्ति की ओर पहल

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के नेतृत्व में ठंड के मौसम में जिला प्रशासन ने सोनहत विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से नाले में बोरी बांधने का कार्य किया था। यह जल संरक्षण की दिशा में एक सफल प्रयोग साबित हुआ। इसी क्रम में अब 28 मार्च को बैकुंठपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पोटेडांड और डोहडा में जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनभागीदारी से जल संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। भारत सरकार द्वारा 'नारी शक्ति से जल शक्ति' अभियान के तहत यह पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को जल संरक्षण की मुख्यधारा में लाना है। भारतीय समाज में नारी और पानी का गहरा संबंध है, क्योंकि घरेलू उपयोग से लेकर कृषि कार्यों तक महिलाएं ही सबसे अधिक जल संसाधनों का उपयोग करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने महिलाओं को जल संरक्षण का नेतृत्व देने जैसे निर्णय ले रहे हैं।

जल संरक्षण के लिए समग्र योजना

इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें ग्राम स्तर पर जन चौपाल का आयोजन, स्वयंसेवकों और युवाओं का चयन, जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करना, जल बहिनी दल के माध्यम से वाटर लेवल सर्वे, ट्रांजिट वॉक कर जल स्रोतों की मैपिंग जैसे कार्य। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने हाल ही में इस विषय पर एक कार्यशाला एवं मैदानी भ्रमण का आयोजन भी किया था। अब आगामी ग्राम वार बैठक में जल संरक्षण के लिए ठोस रणनीति पर अमल किया जाएगा।

कलेक्टर का संकल्प-हर हाल में बचाना है पानी

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि, हमारा उद्देश्य है कि गिरते भूजल स्तर को हर हाल में रोका जाए। पानी बचाने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है और इसके लिए महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि जल संरक्षण कार्यों को ठोस रूप से क्रियान्वित किया जाए।

जल संरक्षण को मिलेगी नई दिशा

'आवा पानी झोंकी' अभियान केवल एक पहल नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है, जिसमें महिलाओं को जल संरक्षण का नेतृत्व सौंपा जाएगा। यह अभियान केवल पानी बचाने का नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देने का एक प्रयास है। जिला प्रशासन की इस नवाचार से निश्चित रूप से जल संरक्षण को एक नई दिशा मिलेगी।

सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्य वाही क्रो लेकर एसडीएम क्रो ज्ञापते सोपते राजपूत समाज के लोग

मरुधर विशेष

एस सैनी बावल सांसद रामजीलाल द्वारा राणा सांगा के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के विरोध मे छोटूराम चौक पर राजपूत समाज के लोगो ने पुतला फूककर विरोध किया राजपूत सभा प्रधान कुलदीप चौहान ने बताया की रामजीलाल सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की हैं उससे राजपूत समाज मे रोष हैं उन्होंने कहा महापुरुषों का अपमान किसी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा इसी क्रो लेकर छोटूराम चौक पर लोग इकठ्ठा हुए और सपा सांसद रामजीलाल के खिलाफ नारेबाजी करके पुतला दहन किया था उन्होंने कहा राणा सांगा ने अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए थे रामजीलाल क्रो इतिहास पढ़ने की ज़रूरत हैं समाज के लोगो ने एसडीएम क्रो ज्ञापन सोपकर सांसद के खिलाफ कार्य वाही करने की मांग की गई इस अवसर पर कुलदीप चौहान कप्तान पूर्ण सिंह नाहर सिंह तवर भीम सिंह चौहान राजेश चौहान उदय सिंह अनिल अत्रि सहित अनेक लोग मौजूद रहे

राजस्थान दिवस समारोह सप्ताह के तहत जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का हुआ आयोजन

जिला स्तरीय कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस एवं व्हीलचेयर और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को किये पट्टे वितरित

मरुधर विशेष

संवाददाता सलीम खान डीग, - राजस्थान दिवस समारोह की श्रृंखला में गुरुवार को जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन डीग स्थित एमएजे कॉलेज के सभागार में किया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के लाभार्थियों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से हुआ सीधा प्रसारण

इस अवसर पर भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। अंत्योदय कल्याण समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 92 हजार निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये का हस्तांतरण, डांग, मंगरा एवं मेवात क्षेत्रीय योजना हेतु 300 करोड़ रुपये, दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हीलचेयर एवं असिस्टिव डिवाइस, 20 हजार परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना में पट्टा वितरण, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरण किया गया और ग्रामीण विकास का नया ई - वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल एप का शुभारंभ किया गया। साथ ही प. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना,दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगजनों हेतु समान अवसर नीति का विमोचन, एमएलए लैड योजना के तहत विधायक सुनवाई केंद्र, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली, मा योजना के तहत न्यू पैकेज एवं मा नेत्र वाउचर योजना तथा गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना के दिशा निर्देश भी जारी किए गए।

जिले के लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत लगभग 2400 लाभार्थियों पट्टों का वितरण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम में इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर - 8, टॉयसाइकिल - 38, व्हील चेयर - 4, स्मार्ट कैन -. 2 एवं 1 श्रवण यन्त्र वितरित किये गए। कार्यक्रम में जिला कलक्टर उत्सव कौशल, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परीवीक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह, एसीपी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विकास शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी तादाद में लाभार्थी मौजूद रहे।

शुक्रवार को सुशासन उत्सव का होगा आयोजन

राजस्थान दिवस समारोह की कड़ी में जिला स्तरीय 'सुशासन उत्सव' का आयोजन गुरुवार को दोपहर 12.00 बजे से किया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कुशलगढ़ की प्रथम बैठक संपन्न, हिंदू नववर्ष की शोभायात्रा को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा

मरुधर विशेष

अरुण जोशी ब्यूरो चीफ बांसवाड़ा कुशलगढ़ : भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कुशलगढ़ की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार ने नवगठित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। बैठक में संगठन की आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा करते हुए हिंदू नववर्ष की शोभायात्रा के भव्य स्वागत को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में अध्यक्ष रेखा जोशी, उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, रमेश तलेसरा, ललिता सोनी, मुस्ताक मकरानी, महावीर कोठारी, केजार समेति, हितेश पडियार, महेंद्र प्रतापसिंह झाला व रितेश बम, महामंत्री दिलीप टेलर व राघवेश चरपोटा, मंत्री रितेश गादिया, प्रीतेश पंड्या, मीना चौहान, निर्मला बाग, भावेश आहरी, महेश प्रजापत, गोवर्धन राठौड़ व महेश भाई, कोषाध्यक्ष मुकेश पंचाल एवं मीडिया प्रभारी रोनक टेलर उपस्थित रहे।बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। अंत में महामंत्री दिलीप टेलर ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

विद्यास्थली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में दूसरे दिन भी हुई छात्र-छात्राओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित

मरुधर विशेष । दिनेश लेखी

कठूमर। विद्यास्थली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चार द्विवसीय उमंग कार्यक्रम के अन्तर्गत गुरूवार को द्वितीय दिवस पर छात्र वर्ग में क्रिकेट व कबड्डी डी और छात्रा वर्ग में रससाकशी, चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर मेहन्दी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. रोहिताश्व यादव ने प्रतियोगी छात्रों का मनोबल बढ़ाया एवं द्वितीय दिवस के समापन पर खेलों के हमारे जीवन में महत्व के बारे में छात्रों को अवगत कराया। इस मौके पर दिनेश, अभिलाषा शर्मा, छोटेलाल जॉगिड, मानसिंह, प्रमोद, मनोज, सचिन, कुलदीप, अनुज मनीष, राजेश पक्षराम, मुकुल कटारा, संतोष पंचोली, डॉ. माया मैडम, पूजा शर्मा, सरिता शर्मा, जया खण्डेलवाल, सतेन्द्र रक्षवाल, रामावतार यादव, राजेश जैमन एवं समस्त कर्मचारियों ने अपना सहयोग किया।

बिल्ली के डर से गर्म दूध के भगोने पर गिरी बालिका, हुई मौत

मरुधर विशेष

कामां। कस्बां के अगमा मौहल्ला में गर्म दूध से झुलसी 3 वर्षीय बालिका की जयपुर इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कस्बां अगमा मौहल्ला निवासी जीतेन्द्र सिंह फौजी की 3 वर्षीय पुत्री सारिका बीती रात को अपने मकान की छत पर खेल रही थी कि तभी छत पर बिल्ली के आने से वह डर गई और उसके पास रखे गर्म दूध के भगोने के ऊपर गिर गई। जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। जिसको परिजनों ने कामां के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने उसे भरतपुर रैफर कर दिया। जहां जयपुर के जेकेलोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन,पशुपालकों को पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के प्रति किया जागरूक

आयोजनों से विद्यार्थियों में सेवा भाव, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं ग्रामीण जीवन के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है : डॉ.कुमारी आशा

मरुधर विशेष

विजय सिंह /मोहम्मद शकील किशनगढ़ बास शहर के तिजारा सड़क मार्ग पर स्थित गांव मांचा में जी.एल.एम. कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ बास में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस शिविर के छठे दिन गुरुवार को विद्यार्थियों द्वारा "एक दिवसीय पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य, देखभाल एवं बीमारियों की रोकथाम के प्रति जागरूक करना था। शिविर के दौरान कृषि महाविद्यालय के शिक्षकों एवं क्षात्रों द्वारा पशुओं के नियमित टीकाकरण, पौष्टिक आहार, स्वच्छता एवं सामान्य बीमारियों के लक्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही पशुपालकों

के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। महाविद्यालय के छात्रों ने ग्रामीणों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। ग्रामीणजन एवं पशुपालकों ने शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया और शिविर की सराहना की। प्राचार्या डॉ.कुमारी आशा ने कहा कि शिविर के अंतर्गत इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में सेवा भाव, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं ग्रामीण जीवन के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। इस अवसर पर कॉलेज के संकाय सदस्य जगजीवन यादव, सनोज कुमार, दीपक मौर्य, संदीप निगानिया, मुहम्मद आरिफ, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कन्हैया कुमार, बच्चूराम सारस्वत सहित सभी शिक्षकगण एवं स्टाफ मौजूद रहा।

कठूमर प्रधान संगम चौधरी को हाईकोर्ट से मिली राहतः निलंबन पर दिया स्थगन आदेश, प्रधानी रहेगी बरकरार

मरुधर विशेष

दिनेश लेखी कठूमर। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर कठूमर प्रधान संगम चौधरी का निलंबन निरस्त 27 फरवरी को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने कठूमर पंचायत समिति के प्रधान संगम चौधरी को अनियमितताओं की जांच के बाद निलंबित कर दिया था। गुरूवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबन पर स्थगन आदेश दिया। पुनः प्रधान पद पर संगम चौधरी रहेंगी। निलंबन का स्थगन आदेश ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कठूमर प्रधान के पूर्व निलंबन का स्थगन आदेश दिया है। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद सतीश चौधरी एवं उप प्रधान विश्वेंद्र चौधरी का ने मुंह मीठा करवाकर व माला पहना कर स्वागत किया और बधाई दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर कि है। संगम चौधरी ने इस आदेश को सत्य की जीत बताया है। गौरतलब है कि संगम चौधरी पत्नी विश्वेंद्र सिंह प्रधान पंचायत समिति, कठूमर ने राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3425/2025 के अनिल मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता यशोधर पांडे ने बताया कि न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने आदेश अनुसार राज्य अधिवक्ता 27 फरवरी 2025 को लगाए गए आदेश को वापस लेना चाहते हैं, साथ ही यदि आवश्यक हो तो नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। इसलिए 27 फरवरी 2025 का आदेश निरस्त किया गया।

खैरथल महाविद्यालय की पूर्व छात्रा रिंकी खातून देश की संसद में करेंगी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

छात्रा रिंकी खातून ने राज्यस्तरीय विकसित भारत युवा संसद में प्राप्त किया तृतीय स्थान,राज्य विधानसभा के अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी ने रिंकी खातून को किया सम्मानित

मरुधर विशेष

विजय सिंह /मोहम्मद शकील खैरथल । भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद प्रतियोगिता में शामिल होकर खैरथल महाविद्यालय की पूर्व छात्रा रिंकी खातून ने राजस्थान की विधानसभा में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में भारतीय संविधान के 75 वर्ष विषय पर बोलते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले युवा 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच राष्ट्रीय स्तर पर देश की राजधानी में भारतीय संसद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विचार रखेंगे। प्राचार्य डॉ. नीतू जेवरिया ने बताया कि रिंकी खातून राज्यस्तरीय कार्यक्रम में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र के युवाओं का देश की संसद में

प्रतिनिधित्व करेंगी यह पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दीपक चंदवानी ने बताया कि रिंकी खातून ने यह उपलब्धि राज्य स्तर के 140 युवाओं के बीच अपना पक्ष रखते हुए प्राप्त की है। कार्यक्रम के समापन पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी ने रिंकी खातून को सम्मानित किया। रिंकी खातून की इस उपलब्धि पर पूरे महाविद्यालय, उनके परिवार व पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रिंकी खातून ने अपनी उपलब्धि का श्रेय

अपनी माता मुन्नी और पिता चुन्नू खान के साथ-साथ अपने शिक्षकों, शुभचिंतकों, जिला युवा अधिकारी पंकज यादव, एनएसएस जिला समन्वयक मंजू शर्मा तथा मार्गदर्शक डॉ. दीपक चंदवानी तथा राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य गौरव जैन को दिया है।

घर घर जाकर नव वर्ष पर्व के उपलक्ष में निकलने वाली शोभा यात्रा मे शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया

मरुधर विशेष

अरुण जोशी ब्यूरो चीफ बांसवाड़ा कुशलगढ़ः आज विश्व हिन्दू परिषद की विभागीय सतसंग प्रमुख मिथलेश कौशिक द्वारा विधुत नगर कॉलोनी मे मातृशक्ति के साथ जाकर घर घर 30 मार्च नव वर्ष के उपलक्ष निकलने वाली शोभा यात्रा मे शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। वहाँ मैदान मे खेल रहे नवयुवक

लड़को को भी निमंत्रण दिया और नए साल के बारे बताया जिसमें उपस्थितिविभागीय सतसंग प्रमुख मितलेश जी कौशिक स्वयं उपस्थिति थी साथ ही ज़िला बाल सस्कार साधना देवड़ा संध्या रस्तोगी चंदा सिंह सीमा दवे मातृशक्ति की सभी मातृशक्ति उपस्थित रही।

वाइज प्रिंसिपल से पदोन्नत प्रिंसिपल को उसी स्कूल में प्रिंसिपल के रिक्त पद किया जावे पदस्थापित

मरुधर विशेष

अरुण जोशी ब्यूरो चीफ बांसवाड़ा कुशलगढ़ः बांसवाडा वाइज प्रिंसिपल के पद को डाइंग केडर घोषित कर इसे समाप्त करने तथा उन सभी को प्रिंसिपल पद पर पदोंन्नति प्रदान करने में पदस्थापन हेतु 4055 वाइज प्रिंसिपलों की पुनः काउंसिलिंग करने की प्रक्रिया करना इन्हें प्रताड़ित करने जैसी प्रतीत हो रही है।यदि इन्हें वाइज प्रिंसिपल के स्थान पर पहले ही पूर्व नियमो के तहत प्रिंसिपल बनाया जाता तो इन्हें बार बार काउंसिलिंग प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता व एक वर्ष से कम समय मे दोबारा तबादला नहीं होता। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामस बांसवाडा के जिलाध्यक्ष श्री अनिल पंडया ने बताया पूर्व में विभाग ने इन्हें व्याख्याता से वाइज प्रिंसिपल के पद पर पदोंन्नति प्रदान की उस समय ऐसी स्कूलो में पदस्थापन दिया जहां पहले से ही प्रिंसिपल के पद भरे हुए है। जबकि होना यह चाहिए था कि जहाँ प्रिंसिपल के पद रिक्त है उन्ही विद्यालयो में वाइज प्रिंसिपल के पद पर इन्हें लगाया जाता तो अब उन सभी को उन्ही विद्यालयो में प्रिंसिपल के रिक्त पद पर समायोजन किया जा सकता था। किन्तु विभाग ने वाह वाई लूटने के लिए जहाँ पहले से प्रिंसिपल कार्यरत है उन स्कूलो में भी पदस्थापन दे दिये।अब इनका एक साल भी नहीं हुआ और वाइज प्रिंसिपल का पद खत्म कर प्रिंसिपल के पद पर पदस्थापन देने पुनः काउंसिलिंग के जरिये तबादला करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।इससे कई वाइज प्रिंसिपलो को दूरस्थ पदस्थापन मिलने की गूंज से आहत होते दिखाई पड़ रहे है। पंडया ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री को पत्र भेजकर माँग की है कि जिन विद्यालयो में प्रिंसिपल का पद भरा हुआ है, वहां वाइज प्रिंसिपल कार्यरत है तो उन्हें पदोंन्नति पर अन्य विद्यालय में काउंसिलिंग कर पदस्थापन देना जायज है किंतु जिन विद्यालयो में प्रिंसिपल का पद पहले से ही रिक्त है। वहाँ यदि कोई वाइज प्रिंसिपल कार्यरत है तो उन्हे पदोंन्नति पर यथास्थान उसी स्कूल में प्रिंसिपल के रिक्त पद पर वहीं समायोजन करना समीचीन होकर न्यायपूर्ण होगा।क्योंकि शिक्षा विभाग पूर्व में ही उन्हें यथावत उन्हीं विद्यालयो में कार्यग्रहण करवा चुका है।यानी प्रिंसिपल के रिक्त पद पर पहले ही यथास्थान पदस्थापन करवा चुका है ऐसे में अब इन्हें पुनः वरीयता सूची में नाम जोड़ते हुए काउंसिलिंग करवाना तबादला करने जैसा है।

दैनिक मरुधर विशेष समाचार पत्र की खबर का हुआ बड़ा असर

जिला कलक्टर किशोर कमार ने तुरंत संज्ञान लेकर खैरथल से रसगन पेहल सड़क मार्ग की करवाई मरम्मत

मरुधर विशेष

विजय सिंह /मोहम्मद शकील खैरथल । दैनिक मरुधर विशेष समाचार पत्र की खबर का हुआ बड़ा असर, जिला कलक्टर किशोर कमार ने तुरंत संज्ञान लेकर पेहल रास्ते कि करवाई मरम्मत, खैरथल से रसगन पेहल सड़क मार्ग पर जाने के लिए ग्राम हुसैनपुर बस स्टैंड पर गांव का गंदा पानी मेंन सड़क पर गड्ढों में भरा रहने से सडक पर कीचड़ हो गई इससे आने जाने वाले राहगीरों को पिछले लंबे समय से काफी परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था लेकिन जिला कलक्टर ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। आमजन की समस्याओं को लेकर दैनिक मरुधर विशेष समाचार पत्र में 24 मार्च को प्रमुखता से छपी खबर विकास की गंगा में डुबकी लगाकर राहगीर हो रहे

प्रादेशिक

विकास की गंगा में डुबकी लगाकर राहगीर हो रहे हैं चोटिल, जिला कलक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन सोया कुंभकर्णी नींद में

चोटिल, जिला कलक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन सोया कुंभकर्णी नींद में, ग्रामीणों ने दी चेतावनी, तीन दिन में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सड़क मार्ग पर जाम लगाकर किया जाएगा विरोध प्रदर्शन, कार्यालय में बैठे अधिकारियों को नहीं है जिला कलक्टर का डर, नगर परिषद खैरथल के वार्ड नंबर दो हुसैनपुर का गंदा पानी पेहल सड़क मार्ग पर भरने से जहांगीर परेशान खबर पर जिला कलक्टर किशोर कुमार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आमजन को समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद खैरथल को सड़क मरम्मत कार्य करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद खैरथल द्वारा सड़क का दुरुस्तीकरण किया गया। नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि खैरथल से रसगन पेहल रास्ते पर जाने के लिए ग्राम हुसैनपुर बस स्टैंड पर गांव का गंदा पानी मेंन रोड़ पर भरा

सड़क निर्माण से पूर्व की स्थिति

ग्रेवल सडक निर्माण के पश्चात

हुआ है जिससे सडक पर कीचड़ हो गई इससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। यह रास्ता खैरथल जिला मुख्यालय को लगभग 15 गांव को जोड़ता है जिस पर लगभग हजारों ग्राम वासी रोजाना दैनिक मजदूरी और काम के लिए तथा छात्र-छात्रा रोजाना स्कूल में शिक्षा हेतु खैरथल आते है, जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दैनिक जनसुनवाई में इस समस्या से अवगत कराया जिस पर आमजन को समस्या से तुरंत राहत दिलाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के मरम्मत के लिए नगर परिषद खैरथल को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बुधवार को सहायक अभियंता भूपेंद्र गुर्जर और कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा द्वारा देर रात तक सड़क का दुरुस्तीकरण कार्य करवाया गया तथा सड़क को मोटरेबल बनाया गया। जिसमें सड़क पर भरे पानी को निकाल कर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया ताकि आमजन को तुरंत इस समस्या से राहत मिल सके। कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा ने बताया कि लगभग ढाई सौ फीट रोड का दुरस्तीकरण किया गया जिस पर लगभग 2 फीट गंदा पानी भरा हुआ था।

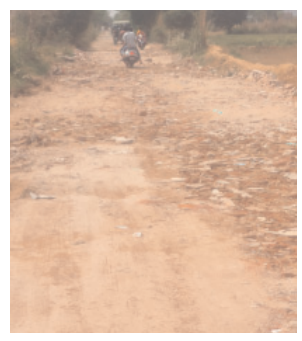

कुशलगढ़ में दिनदहाड़े सूने मकान में चोरी की वारदात

मरुधर विशेष

अरुण जोशी ब्यूरो चीफ बांसवाड़ा कुशलगढ़ः बीएसएनल ऑफिस के पास स्थित एक मकान में दिनदहाड़े चोरी की वारदात हुई। यह घटना सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे के बीच में हुई हे। जब घर के मालिक अहमद रजा खान पठान और उनकी पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में टीचर हैं। अहमद रजा खान पठान ने बताया कि वह सुबह करीब 9:30 बजे अपने घर से बाहर गए थे और स्कूल की ओर रुख किया था। घर का

दरवाजा बंद था बाहर से ताला लगा हुआ था और घर में कोई भी नहीं था। इसे देखकर चोरों ने मौका देखकर चोरी करने की योजना बनाई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और पूरे घर की तलाशी ली। अलमारी में रखा सामान सब इधर उधर कर दिया कुछ नहीं मिला।दूसरे कमरे में चोरी के दौरान चोरों को दो मोबाइल फोन मिले। लेकिन घर में कोई कीमती सामान न मिलने के कारण बड़ी हानि से बचा। चोरों ने घर में छानबीन करते हुए अन्य वस्तुओं को छुआ। लेकिन अधिकतर सामान सुरक्षित रहा। ये घटना जो हुई हे वो सूरत बस स्टैंड के पास हे। पूरे दिन लोगों का आवागमन होता रहता हैं। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माजरी खुर्द में रसोई भवन निर्माण का लोकार्पण हुआ सीएसआर फंड से कराया जा रहा निर्माण कार्य

मरुधर विशेष

नीमराना (सुनील मेघवाल) नीमराना उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माजरी खुर्द में नीमराना स्टील सर्विस सैंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सीएसआर फंड से निर्मित रसोई

भवन का लोकार्पण गुरुवार को एम डी हिरोशी इतो,एच आर हैड ब्रजेश यादव,एक्जीक्यूटिव हैड स्वाती यादव, एच आर अनीश यादव,राजेश यादव ठेकेदार के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक दान सिंह यादव ने बताया कि एन एस एस आई कंपनी नीमराना के द्वारा गत वर्ष शौचालय का भी निर्माण करवाया गया था।एसडीएमसी सदस्यगणों व विद्यालय स्टाफ के द्वारा अतिथियों का पुष्प भेंट कर एवं माला, साफा पहनाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया।मंच संचालन रेखा यादव ने किया।इस अवसर पर पीओ दिनेश यादव, प्रधानाध्यापक दानसिंह यादव,कंवर सिंह, रामेश्वर सुबेदार, नरेन्द्र उपसरपंच,महेंद्र यादव,सुरेश यादव,बस्तीराम पंच,सुरेश शर्मा,अरूण यादव वार्डन, प्रवीण यादव समाज सेवी,रामधन यादव,रिची यादव,राजबाला,हेमलता शर्मा,पिंकी,बीना यादव,बलजीत यादव व ग्रामीण मौजूद रहे।

Marudharhind24 news Private Limited के लिए महारानी प्रिन्टर्स 17 वैष्णोदेवी नगर कालवाड़ रोड जयपुर से मुद्रित, एवं जीवन सिंह पुरा शाम्दा अलवर से प्रकाशित। मो. 9653906665, 7014373732